



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 25 सितम्बर, 2007 / 4 आश्विन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अप्रैल, 2007

संख्या इण्ड-।।(बी)2-8/2006.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1)विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियों.— (1)इस विभाग की अधिसूचना संख्या: उद्योग-।। (ख) 2-29/95 तारीख 23-07-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कारवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता/—,
अतिवित्त मुख्य सचिव।

उपाबन्ध 'क'

हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन), वर्ग—।।। (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम : विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन)
2. पदों की संख्या : 2(दो)
3. वर्गीकरण : वर्ग—III ;(अराजपत्रित)
4. वेतनमान (विस्तृत रूप में दिया जाए) : 5800—200—7000—220—8100—275—9200 रुपये।
5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन।
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल

प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :-

(क) अनिवार्य अर्हता :- रेशम उत्पादन संगठन में रेशम उत्पादन सक्रिया में पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० (कृषि) या जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान के साथ बी०एस०सी० या इसके समकक्ष।

(ख) वांछनीय अर्हताएं(ए) :- हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :- आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति:-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :- शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा :- मल्वरी अधीक्षकों/अनुसंधान सहायकों/वरिष्ठ रेशम उत्पादन निरीक्षकों/तकनीकी पर्यवेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्तियों की उनके सेवाकाल के आधार पर संवर्गवार पास्परिक वरिष्ठता सूची को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझे जाएंगे/समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

2. इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी। यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :- जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा :- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :-

- (1) **संकल्पना :-** (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) का संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
- (ख) अभ्यर्थी का सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेंवर चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पद का विज्ञापन देकर चयनित किया जाएगा।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थायी आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(11) **देय मानदेय :-** संविदा के आधार पर नियुक्त विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) को मु0 5800/-रूपये जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत की जाएगी। आकस्मिक अवकाश के सिवाए छुट्टी अवधि के लिए कोई राशि संदत नहीं की जाएगी।
!क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मानदेय में 200/-रूपये की बढौतरी अनुज्ञात की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है।

(III) **नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी :-** निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया :-** (क) निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश विकास अधिकारी(रेशम उत्पादन) की विद्यमान रिक्तियों की बावत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सरकार को अग्रिम रूप में सूचित करेगा और कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानकों के अनुसार उनको पूर्ण न्यायोचित देते हुए रिक्तियों को भरने हेतु सरकार का अनुमोदन मागेंगा।

(ख) सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है तो प्रथमतः सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार विभागाध्यक्ष का विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) के रिक्त पद को सविदा के आधार पर केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरने हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करेगी जिसे सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष रिक्त पदों को सविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष भेजेगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :-** चयन सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(VI) **करार :-** अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें :-** (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 5800/-रुपये जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन की दर से सविदात्मक रकम संदत की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा /होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ.) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ज) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक गर्भावस्था प्रसव होने तक उस अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(झ) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :- इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में उद्योग विभाग में विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण :- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा :- लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति :- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्गों या पदों की बावत् शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप:

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **प्रथम पक्षकार** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है) आज तारीख.....को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने प्रथम पक्षकार को लगाया है और **प्रथम पक्षकार** ने विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 5800/-रूपये जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत की जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मानदेय का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार नियुक्त विकास अधिकारी (रेशम उत्पादन) का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department Notification No: Udyog-II(Kha)2-8/2006 Dated: 20 7-2007.....as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th July, 2007

No.Udyog-II (Kha) 2-8/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, in Consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Development Officer (Sericulture), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely: —

1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Development Officer (Sericulture), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Development Officer (Sericulture), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department Notification No. Udyog-II (Kha) 2-29/95 dated 23.07.1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made or done or done or taken these rules.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEVELOPMENT OFFICER (SERICULTURE)(NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH.

1. *Name of the Post* : Development Officer (Sericulture)
2. *Number of Post(s)* : 2 (Two)
3. *Classification* : Class-III (Non-Gazetted)
4. *Scale of Pay* : Rs.5800-200-7000-220-8100-275-9200.(Rs.given in expanded rotation).

5. *Whether "Selection" Post or Non "Selection Post": Non-Selection*

6. *Age for direct recruitment* : Between 18 and 45 years provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations /Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations /Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment :*

(a) **ESSENTIAL QUALIFICATION** :— Must possess B.Sc.(Agriculture) or Bsc. with Zoology/Botany with five years experience in Sericulture operation in Sericulture organisation or its equivalent from a recognised University.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATIONS**:— Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s):—*

Age: Not applicable

E.Q.: Not applicable

9. *Period of probation, if any:*—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:*—100% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment, by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation/transfer is to be made : By promotion from amongst the Mulberry Superintendents /Research Assistants/ Senior Sericulture Inspector/ Technical Supervisor who possess 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade.

For the purpose of promotion a combined seniority list of feeder categories based on length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that:

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment : As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment : A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment: Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to post by contract appointment : —

(I) CONCEPT:-

- (a) Under the policy, Development Officer (Sericulture) in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.
- (b) The candidates will be selected by advertising the vacant post by the concerned recruiting agency i.e. H.P. subordinate Service Selection Board.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
- (d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(II) HONOURARIUM PAYABLE: The Development Officer (Sericulture) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.5800/- +50% DP per month. No amount will be paid of leave period except Casual Leave. An amount of Rs. 200/- as Increase in honorarium for second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY : Director of Industries, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : (a) The Director of Industries, H.P. will inform the Govt. about the existing vacancies of Development Officer (Sericulture) well in advance before the end of the financial year and seek approval to fill up the vacancies by giving full justification for the same according to the work load and norms.

- (b) The request will be considered by the Govt. and if there is any request for transfer in the first instance, the Govt. will fill up the vacancy by transfer of regular incumbent, or otherwise, Govt. will issue "No Objection Certificate" to the Head of Department to fill up the vacant post of Development Officer (Sericulture) on contract basis for one financial year only, which can be extended for year to year by the Govt.
- (c) The Head of the Department after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant post on contract basis will send the requisition to the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS :

Selection will be made by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board.

(VI) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she has to sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS : (a) The Contract Appointee will be paid Contractual amount @ Rs.5800/-+50% DP per month.

- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good.
- (c) Contract appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
- (d) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract Appointee. He / She shall not be entitled for medical reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
- (e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract.
- (f) Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (g) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (h) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./registered Medical practitioner. Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
- (i) Contract appointee will be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Development Officer (Sericulture) in Industries Department at any stage.

16. Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination. N.A.

18. Powers to Relax: Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation

with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure - B

Form of contract /agreement to be executed between the Development Officer (Sericulture)& the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this day of in the year between Sh. / Smt. S/o/D/o Sh.R/o..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Development Officer (Sericulture) on contract basis on the following terms and conditions :

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Development Officer (Sericulture) for a period of 1 year commencing on the day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary.

2. The Contract Appointee will be paid Contractual amount @ Rs.5800/-+50% DP per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual Development Officer (Sericulture) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Development Officer (Sericulture). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. One maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Development Officer (Sericulture) will not be entitled for the honorarium for the period of absence from duty.

7. Transfer of a Development Officer (Sericulture) appointment on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract official shall be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection

with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer.

10. The Employees Group Insurance Scheme EPF /GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.'

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2

 (Name and Full Address)

Signature of the (FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2.

 (Name and Full Address)

Signature of the (SECOND PARTY)

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री छोटा राम, गांव व डाकघर जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए पंचायत अभिलेख धौनकोठी में शादी दर्ज करने बारा।

श्री धर्म सिंह ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि शादी दिनांक 7-7-2007 को मुताविक हिन्दू रिती रिवाज के रीना कुमारी सुपुत्री श्री कृष्ण लाल, निवासी मेन मार्किट, मकान नं० 9 A, वार्ड नं० 8, बिलासपुर (हि० प्र०) के साथ हुई है। और तब से बतौर पति पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख धौनकोठी में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः आम जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 11-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 शून्य

तारीख पेशी 22-10-2007

श्री श्याम लाल पुत्र श्री कांसी राम, न्याईसार, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम पंचायत कोठीपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

2. आम जनता

. फरीकदोयम।

विषय.—मंजना देवी सुपुत्री श्री ओम प्रकाश की शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री श्याम लाल पुत्र श्री कांशी राम, निवासी न्याई सारली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि मेरी शादी मंजना देवी सुपुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी दगसेच से हिन्दु रीति-रिवाज से हुई है। लेकिन गलती से हम शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके। अतः अब शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-07 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्तक्षरी (तहसीलदार) के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति समायत नहीं होगी। अनुपस्थिति की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी। व उपरोक्त शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 6-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
(तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती शुकरदीन सुपुत्री मसरदीन, निवासी वडौण, डाकघर कटौला, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शुकरदीन सुपुत्री श्री मसरदीन, निवासी वडौण, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम सुलताना बीबी का जन्म दिनांक 27-9-2003 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वंश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत एम0सी0 कटौला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को अदालत में असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री..... पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मदन कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री मुरारी लाल सुपुत्र श्री मेद राम, निवासी सअेर, डाकघर नमहोल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुरारी लाल सुपुत्र श्री मेद राम, निवासी सअेर, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम शिवानी का जन्म दिनांक 22-7-2004 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वंश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत एम0सी0 तुंग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को अदालत में असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री..... पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मदन कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री सन्त राम सुपुत्र श्री हिम्मत राम, निवासी तरयाम्वली, डाकघर राण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सन्त राम सुपुत्र श्री हिम्मत राम, निवासी तरयाम्वली, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी जन्म तिथि 9-3-1955 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वंश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत एम0सी0 तरयाम्वली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को अदालत में असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री..... पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मदन कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री डिकू उर्फ डिकमे राम सुपुत्र श्री लख, निवासी तुन्धला, डाकघर दयोशी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री डिकू उर्फ डिकमे राम सुपुत्र श्री लख, निवासी तुन्धला, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी जन्म तिथि 10-3-1955 को हुआ था परन्तु अज्ञानता वंश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत एम0सी0..... के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को अदालत में असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री..... पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मदन कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ईशतहार

ब अदालत श्री मन्जीत शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 20 / 2005

तारीख मरजुआ 20-9-2005

तारीख पेशी 10-10-2007

सर्व श्री हिरा लाल, मेद राम व भूप राम पुत्रगण स्व0 श्री खीवण राम, ग्राम कोट, तहसील शिमला, ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थी।

बनाम

1. सर्वश्री नरायण दास, रूप राम, भूप राम पुत्रगण श्रीमती दर्शनू देवी, सैनू पुत्रियां श्रीमती मालती व सेवती विधवाएं स्व0 श्री मनसा राम, निवासी कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2. सर्वश्री तुलसी राम, सोम दत्त पुत्रगण व श्रीमती द्वारकू पुत्री स्व0 श्री केसरू, निवासी कोट, तहसील शिमला, ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. श्री मस्त राम पुत्र श्री बालक राम, निवासी कोट, तहसील शिमला, ग्रामीण, हिमाचल प्रदेश।
4. श्री हेम दत्त पुत्र श्री पूरनू, निवासी कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), हिमाचल प्रदेश।
5. सर्वश्री गणेश दत्त, दिला राम पुत्रगण, मथरू, शिबी पुत्रियां राम, निवासी कोट, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
6. श्री गंगाधर पुत्र सुहागू पुत्री श्री टिका, निवासी कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
7. श्री भीखू पुत्र श्री बालकू रूप राम दिगम्बरदत्त, बाबू देव, पदम नाथ पुत्रगण चानला, निवासी कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
8. सर्वश्री/श्रीमती मोहन दत्त, गुलाब चन्द, नीला नन्द पुत्रगण नरबदा, सोमा, शान्ती, गंगी, दसोदा, पुत्रियां श्री टेक राम, निवासी कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
. प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 13/30 से 13/35 किता 14 रक्वा 1-03-34 हैक्टेयर खाता/खतौनी नं0 14/36 से 14/39, 45 किता 9 रक्वा तादादी 0-32-60 हैक्टेयर, खाता/खतौनी नं0 15/40 से 15/55 किता 80 तादादी 10-86-03 हैक्टेयर, खाता/खतौनी नं0 16/56 से 16/60 किता 22 रक्वा तादादी 3-21-22 हैक्टेयर कुल रक्वा तादादी 15-43-19 हैक्टेयर वाका मौला कोट तहसील शिमला, ग्रामीण, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

सर्वश्री/हिरा लाल, मेद राम व भूप राम, पुत्रगण स्व0 श्री खीवण राम, ग्राम कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 13/30 से 13/35 किता 14 रक्वा 1-03-34 हैक्टेयर खाता/खतौनी नं0 14/36 से 14/39, 45 किता 9 रक्वा तादादी 0-32-60 हैक्टेयर, खाता/खतौनी नं0 15/40 से 15/55 किता 80 तादादी 10-86-03 हैक्टेयर, खाता/खतौनी नं0 16/56 से 16/60 किता 22 रक्वा तादादी 3-21-22 हैक्टेयर, कुल रक्वा तादादी 15-43-19 हैक्टेयर वाका मौला कोट, तहसील शिमला, (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश बारे प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन तामील हेतु जारी किये गये परन्तु अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी। अतः

अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादियों की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को भू-विभाजन बारे कोई उजर/एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 10-10-2007 को उपराहन 2 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मन्जीत शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग तहसीलदार सोलन, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

इन्तकाल नं0 1489 वाका मौजा जाबल झमरोट, तहसील व जिला सोलन, मकफूद-उल-खबरी वरासत श्री सिन्धु पुत्र श्री थन्कु, निवासी गांव शील, डाकघर देवठी, तहसील व जिला सोलन, बहक जायज वारसान।

उनवान मुकद्दमा :

सुरेश चन्द

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

उनवान मुकद्दमावाला में आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्री जगत राम, निवासी गांव शील, डाकघर देवठी, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, ने अदालत हजा में दरखास्त गुजारी है कि श्री सिन्धु पुत्र श्री थन्कु काफी समय से लापता है तथा उसके जिवित होने या होने का कोई इलम न है। इसलिए उसकी वरासत का इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करवाया जाये। बाद छानबी, सिन्धु पुत्र श्री थन्कु की वरासत का इन्तकाल नं0 1489 वाका मौजा जाबल झमरोट बहक सर्वश्री ख्याली राम, सुरेश चन्द पुत्रान स्व0 श्री जगत राम, संजु पुत्र स्व0 गुलाबी पुत्री स्व0 श्री जगत राम शीला पुत्री स्व0 श्रीमती गुलाबी पुत्री स्व0 श्री जगत राम जायज वारसान दर्ज कर दिया गया है जो जेरे फैसला है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदार को ईतलाह दी जाती है कि यदि किसी को उक्त इन्तकाल सिन्धु पुत्र श्री थन्कु के जायज वारसानों के नाम तस्दीक होने में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन अदालत हजा में दिनांक 2-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आकर पेश कर सकता है अन्यथा बाद में कोई भी उजर/एतराज काबले गौर नहीं होगा तथा इन्तकाल का फैसला हस्व जाब्ता कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 1-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सन्त राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार सोलन),
तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार), कण्डाघाट,
जिला सोलन (हि0 प्र0)

श्री प्रेम सागर पुत्र श्री ईश्वर दत्त, निवासी ग्राम कलोग (शावग), तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश . प्राथी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री प्रेम सागर पुत्र श्री ईश्वर दत्त, निवासी ग्राम कलोग (शावग), तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका सही नाम प्रेम सागर है जबकि राजस्व अभिलेख मौजा सनहेच, तहसील कण्डाघाट में उसका नाम विद्यासागर दर्ज चला आ रहा है जो कि गलत है इसलिए उसके नाम की दुरुस्ती की जाये। सबूत के तौर पर उसने स्कूल का प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, शपथ पत्र, छाया प्रति राशन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर तथा नकल जमाबन्दी शामिल कर रखी है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री प्रेम सागर के नाम की दुरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को या इससे पूर्व इस कार्यालय में आकर प्रस्तुत करें अन्यथा नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह रान्टा,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार),
कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विद्याधर नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)

श्री सेवक राम पुत्र श्री सुरतीया राम, निवासी ग्राम डमढार, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल
प्रदेश . प्राथी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री सेवक राम पुत्र श्री सुरतीया, निवासी ग्राम डमढार, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व रिकार्ड मौजा डमढार, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन में उसका नाम सेवक राम पुत्र श्री सुरतीया दर्ज है जो कि सही दर्ज है। लेकिन उसका नाम मौजा बखोर, परगना पशगांव, तहसील कण्डाघाट में चिडू राम पुत्र श्री सुरतीया दर्ज किया गया है जो कि गलत दर्ज किया गया है। इसलिए उसके नाम की दुरुस्ती की जाये सबूत के तौर पर उसने अपना बयान हलफिया नकल जमाबन्दी मौजा डमढार व बखोर शामिल कर रखी है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री सेवक राम पुत्र श्री सुरतीया, का नाम राजस्व कागजात मौजा बखोर में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2007 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विद्याधर नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)

श्री दीना नाथ पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी ग्राम जेखड़ी, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश . वादी।

बनाम

जनरल पब्लिक (सर्वसाधारण)

. प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री दीना नाथ पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी ग्राम जेखड़ी, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, ने इस न्यायालय में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री कुमारी ज्योति की जन्म तिथि 1-4-2002 है जिसका जन्म जेखड़ी गांव में हुआ है लेकिन जन्म तिथि समय पर ग्राम पंचायत सायरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई जा सकी है। अब दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस के दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा अदम हाजरी में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जायेगी और उपरोक्त कुमारी ज्योति का नाम एवं जन्म तिथि सम्बन्धित के रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 10-9-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह रान्टा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री चौधरी राम, गांव जवाल, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) .वादी।

बनाम

आम जनता

.प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री चौधरी राम, गांव जवाल, उप-तहसील भरवाई, ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि प्रार्थी की पुत्री रेणु कुमारी का जन्म 3-1-2003 को हुआ था जिसका ईन्द्राज पंचायत अभिलेख में अज्ञानता वश दर्ज नहीं कर सका है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित भरवाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में प्रार्थना-पत्र श्री सुरिन्दर कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 13-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राम कुमार पुत्र श्री वावू राम, गांव किन्नू, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) .वादी।

बनाम

आम जनता

.प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राम कुमार पुत्र श्री वावू राम, गांव किल्लू, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि प्रार्थी का पुत्र निखिल पुत्र श्री राज कुमार का जन्म 7-12-2003 को हुआ था जिसका ईन्द्राज पंचायत अभिलेख में अज्ञानता वश दर्ज नहीं कर सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित भरवाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सुरत में प्रार्थना-पत्र श्री राम कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

आज दिनांक 12-9-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 27th August, 2007

No. HFW-B(G)1-3/2007.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of following 69 posts of Registrars/Demonstrators in various departments in IGMC, Shimla in the pay-scale of Rs. 7880-13,500/- with initial start of Rs.8,000/- per month :-

Sr. No.	Name of Department	No. of posts
1.	Anaesthesia	9
2.	Anatomy	1
3.	Bio-Chemistry	1
4.	CTVS	1
5.	Cardiology	1
6.	Medicine	1
7.	Microbiology	1
8.	OBG	5
9.	Orthopedics	5
10.	Psychiatry	2
11.	Physiology	1
12.	Pul. Medicine (Chest & TB)	2
13.	Radiology	2
14.	Radiotherapy	1
15.	Casualty	12
16.	Surgery	4
17.	Urology	4
18.	Neurosurgery	6
19.	Plastic Surgery	4
20.	Pediatric Surgery	4
21.	Nephrology	2
	Total	69

The expenditure on the creation of these posts will be met out of sanctioned budget under Major Head: 2210-Medical & Public Health, 105-Allopathy-05- Medical Education & Research, 01-IGMC, Shimla(Plan) for the year 2007-08.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 2077-Fin-F/2007, dated 7.7.2007 and U.O. No. 50468151-Fin-F/2007, dated 7.7.2007.

Shimla-2, the 27August, 2007

No. HFW-B(G)1-3/2007.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of following 64 posts of Registrars/Demonstrators in various departments in Dr. RPGMC, Kangra at Tanda in the pay-scale of Rs. 7880-13,500/- with initial start of Rs.8,000/- per month :-

Sr. No.	Name of Department	No. of Posts
1.	Anaesthesia	4
2.	Anatomy	2
3.	Bio-Chemistry	1
4.	Comm. Medicine	1
5.	Dermatology (Skin & VD)	2
6.	ENT	2
7.	Forensic Medicine	1
8.	Medicine	4
10.	Microbiology	3
11.	OBG	4
12.	Ophthalmology	2
13.	Orthopedics	6
14.	Pediatrics	6
15.	Pathology	4
16.	Pharmacology	1
17.	Psychiatry	3
18.	Physiology	2
19.	Pul. Medicine (Chest & TB)	3
20.	Radiology	6
21.	Surgery	4
22.	Dentistry	3
	Total	64

The expenditure on the creation of these posts will be met out of sanctioned budget under Major Head: 2210-Medical & Public Health, 105-Allopathy-05- Medical Education & Research, 06-Dr. Rajender Prasad Medical College, Tanda (Plan) for the year 2007-08.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 2077-Fin-F/2007, dated 7.7.2007.

ADDENDUM

Shimla-2, the 19th September, 2007

No. HFW-B(G)1-3/2007.—The words “3 posts each in the Departments of Orthopaedics, General Surgery, General Medicine and Paediatrics” be read with 12 posts in Casualty at Sr.No. 15 of this Department Notification of even No. dated 27.8.2007 in respect of Indira Gandhi Medical College, Shimla.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

TRANSPORT DEPARTMENT**ORDER***Shimla-2 the 20th September, 2007*

NO. TPT-A(3)2/2002-Part-I.— In continuation of this department order NO: TPT-A(3)2/2002, dated 27/09/2004, The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that permit fee, if any, charged under Rule-68 and Rule-69 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 for the period 9/8/2004 to 27/09/2004 under the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second) Amendment Rules, 2004 may kindly be adjusted in the further renewal of the permit.

By order,
AVAY SHUKLA, I.A.S.
Additional Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001**NOTIFICATIONS***Shimla, the 6th September, 2007*

No.HHC/Admn.16 (7)74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Sh. Vinod Kumar Soni, Advocate as Oath Commissioner at Dharmshala and Sh. Manoj Sharma, Advocate as Oath Commissioner at Kangra, H.P., made vide Notifications No.HHC/Admn.16(7)74-VIII10259-68 dated 15.5.2007 and 19209-17, dated 6.9.2006, respectively, with immediate effect.

Shimla, the 5th September, 2007

No.HHC/Admn.16 (15)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Sh. Jeevesh Dutt Sharma as Oath Commissioner at Kandaghat, District Solan, H.P. made vide Notification No. HHC/Admn. 16 (15)74-III- 21321-27, dated 7.10.2005, with immediate effect.

Shimla the 3rd September, 2007

No.HHC/Admn.6(18)77-Part.—In exercise of the powers vested under Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Ist Class, upon all the District Magistrates/Executive Magistrates (not below the rank of SDM(s), in the State of Himachal Pradesh, except the District Magistrate, Shimla, from 7.9.2007 to 9.9.2007, for disposal of urgent criminal matters i.e. remands etc., within their jurisdiction.

Shimla, the 5th September, 2007

No.HHC/Admn.16 (13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, has been pleased to cancel the appointment of Sh. Raman Kumar, Advocate as Oath Commissioner at Chopal, H.P., made vide Notification No.HHC/Admn.16(13)74-VI-20693-20701 dated 23.9.2006, with immediate effect.

By order,
 Sd/-
Registrar General.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचनाएं**

शिमला-171002, 11 सितम्बर, 2007

संख्या: सिंचाई 11-121/2006-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा काठगड़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा न०	क्षेत्र हैक्टियर में
कांगड़ा	इन्दौरा	काठगड़	70/1	0-05-15
			69/1	0-00-49
			73/1	0-00-48
			146/1	0-00-76
			67/1	0-00-38
			60/1	0-03-97
			434/1	0-00-26
			431/1	0-01-22
			419/1	0-00-22
			424/1	0-06-96
			423/1	0-00-06
			460/1	0-01-80
			465/1	0-03-53
			492/1	0-03-57
			534/1	0-02-94
			536/1	0-01-92
			538/1	0-00-90
			539/1	0-03-90
			980/1	0-00-50
			542/1	0-00-72
			981/1	0-01-40
			982/1	0-00-49
			982/1/1	0-00-65
			984/1	0-01-10
			958/1	0-02-70
			957/1	0-00-37

		953/1	0-01-58
		952/1	0-03-33
		951/1	0-00-22
		908/1	0-03-78
		905/1	0-05-25
		65/1	0-01-18
		64/1	0-01-65
		66/1	0-00-26
		148/1	0-04-75
		163/1	0-00-85
		164/1	0-01-21
		421/1	0-02-28
		485/1	0-02-20
		160/1	0-01-68
		161/1	0-04-90
		<u>162/1</u>	<u>0-03-26</u>
		<u>किता-42</u>	<u>0-84-52</u> हे०

शिमला-171002, 26 जुलाई, 2007

संख्या: सिंचाई 11-161/2007-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बासा हड़ियाला तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समारहता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र हैक्टेयर
कांगड़ा	नूरपुर	बासा हड़ियाला	550/1/1	0-00-27
			551/1	0-00-60
			553/1	0-00-58
			554/1	0-05-71
			<u>556/1</u>	<u>0-00-57</u>
			<u>किता-5</u>	<u>0-07-73</u>

शुद्धि पत्र

संख्या: सिंचाई 11-27/2007-कांगड़ा.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-8-2007 में गांव—झण्डूता दोयम, तहसील—झण्डूता, जिला—बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना रोपड़ी भाखड़ेजल भण्डारण के स्थान पर महाल ढन मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा नलकूप न0 1 पढ़ा जाये।

शिमला-171002, 24 सितम्बर, 2007

संख्या: सिंचाई 11-15/2006-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल घण्डरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
कांगड़ा	इन्दौरा	घण्डरा	591/1	0-31-20 है०

शिमला-171002, 24 सितम्बर, 2007

संख्या: सिंचाई 11-58/2007-बिलासपुर.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव झण्डूता दोयम, तहसील—झण्डूता, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना रोपड़ी—भाखड़े जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता,

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बीघे में
बिलासपुर	झण्डूता	झण्डूता दोयम	493	0-28-86

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव ।

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 सितम्बर, 2007

संख्या : फिश-ए(3)-1/2007.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में अधीक्षक ग्रेड-॥, वर्ग-॥ (अराजपत्रित), के पद के लिए उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, अधीक्षक ग्रेड-॥ वर्ग-॥, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
सचिव ।

उपबन्ध - " क "

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में अधीक्षक ग्रेड-॥, वर्ग-॥ (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

- 1 पद का नाम : अधीक्षक ग्रेड-॥
- 2 पदों की संख्या : 04 (चार)
- 3 वर्गीकरण : वर्ग-॥ (अराजपत्रित)
- 4 वेतनमान : 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपये ।
- 5 चयन अथवा अचयन पद : अचयन
- 6 सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगीया प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता: शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा: वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

- (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे ;

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल ,रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेटनौन-टैक्नीकल सर्विसिजद्ध रूल्ज,1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन ,रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिजद्ध रूल्ज,1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

- (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा: लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : लागू नहीं ।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों /अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of Government Notification no. Fish-A(3)-1/2007, dated 18-9-2007 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India]

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2007

No. Fish-A(3)-1/2007 .—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the HP Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Fisheries, HP as per Annexure-A, namely :-

1 Short title and Commencement.— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries Department, Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2007.

(ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

By order,
Sd/-
Secretary.

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT
GRADE-II, CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES**

1. *Name of the post:* Superintendent Grade-II
2. *Numbers of posts :* 04 (Four)
3. *Classification :* Class-II (Non-Gazetted)
4. *Scale of pay :* Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
5. *Whether selection post or Non-Selection :* Non-selection post
6. *Age for direct recruitment :* Not applicable.
7. *Minimum Education and other qualification required for direct recruits:* Not Applicable
8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:* Not applicable
9. *Period of probation, if any:* Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:* 100 % by Promotion.
11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made:* By promotion from amongst the Senior Assistants with 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that

In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal State Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a departmental promotion committee exists, what is its Composition:* As may be constituted by the Government, from time to time

13. *Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments:* As required under the Law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment :* Not applicable

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment:* Not applicable.

16. *Reservation.* The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the HP Government from time to time.

17. *Departmental Examination :* Not applicable

18. *Power to relax:* Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of rules with respect to any class or category of persons or posts.

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 21st September, 2007

No.Per(A-IV)-F(11)-2/94.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of the decision as contained in this Department's Notification of even number dated 20th September, 2007, is

pleased to re-designate the following Himachal Pradesh Administrative Service Officers on completion of requisite span of service prescribed for giving higher designations, with immediate effect, in the public interest:-

Sr. No.	Name & present designation of the Officer	New Designation
1.	Shri Rakesh Sharma, HPAS, Secretary, State Transport Authority-cum-Joint Commissioner (Transport), Himachal Pradesh, Shimla.	Secretary, State Transport Authority-cum-Additional Commissioner (Transport), Himachal Pradesh, Shimla.
2.	Shri Subhash Chander Pal, HPAS, Joint Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.	Additional Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.
3.	Shri Man Singh Verma, HPAS, Joint Director, Indira Gandhi Medical College and Medical Education & Research, Shimla.	Additional Director, Indira Gandhi Medical College and Medical Education & Research, Shimla.
4.	Shri K.K. Khanna, HPAS, Joint Director, Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh, Shimla.	Additional Director, Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh, Shimla.
5.	Shri Bihari Lal Raghav, HPAS, Joint Director, Urban Development, Himachal Pradesh, Shimla.	Additional Director, Urban Development, Himachal Pradesh, Shimla.
6.	Shri Karam Dass Rana, HPAS, Joint Director, Industries, Himachal Pradesh, Shimla.	Additional Director, Industries, Himachal Pradesh, Shimla.
7.	Shri Chaman Ditta, HPAS, Deputy Director (Rural Development)-cum-Ex-Officio Deputy Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.	Joint Director (Rural Development)-cum-Ex-Officio Deputy Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.
8.	Shri Ashwani Ramesh, HPAS, Deputy (Transport) Commissioner-cum-Regional Transport Officer (HQ), Shimla.	Joint (Transport) Commissioner-cum-Regional Transport Officer (HQ), Shimla.
9.	Smt. Prabha Rajeev, HPAS, Deputy Director, Social Justice & Empowerment (ICDS), Himachal Pradesh, Shimla.	Joint Director, Social Justice & Empowerment (ICDS), Himachal Pradesh, Shimla.

These Officers will continue to function as here-to-fore in their respective Department(s) and consequent upon the aforesaid designation(s), no additional financial benefit will be permissible to the concerned Officer(s).

By order,
RAVI DHINGRA,
Chief Secretary.